भारत में डेयरी उद्योग : सफलताएं और चुनौतियां

—गौरव कुमार

तमाम सफलताओं के बावजूद डेयरी क्षेत्र में शामिल किसान और पशुपालक आज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। न उनके पास उचित तकनीक पहुंच पाई है ना चारा और पोषण सुरक्षा है। ऐसे में कल्याणकारी नीतियों को अमल में लाने की सख्त जरूरत है।

आज भारत में कृषि के सहयोगी व्यवसाय के रूप में डेयरी उद्योग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशु धन है, विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है और भारत की जलवायु इस क्रियाकलाप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। देश में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए समय–समय पर काफी प्रयास किए जाते रहे हैं। इन सारे प्रयासों का नतीजा है कि दसवीं योजना के अंत तक दुग्ध उत्पादन 102.6 मिलियन टन से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 127.9 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया। यह गौर करने लायक है कि आज भी देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। हालांकि इन्हें अब सहकारिता के अंतर्गत लाया जा रहा है, और मार्च 2014 तक लगभग 15.46 मिलियन किसानों को 162186 ग्राम–स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के तहत लाया गया है। सहकारी दुग्ध संघों ने पिछले वर्ष के 33.5 मिलियन किलोग्राम की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 34.2 मिलियन किलोग्राम दूध प्रतिदिन के औसत से खरीदा है और 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सहकारी क्षेत्रों द्वारा तरल दूध की बिक्री वर्ष 2013–14 के दौरान 29.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5.8 प्रतिशत अधिक है। आज भारत में दूध का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित हो चुका है जो करीब 800 शहरों और कस्बों तक ताजे दूध की आपूर्ति करता है।

सरकारी प्रयास

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने सिद्धांततः पशुपालन क्षेत्र के लिए 7628 करोड़ रुपये, डेयरी क्षेत्र के लिए 4976 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके अलावा कई वार्षिक और समय–समय पर जारी की गई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डेयरी विभाग द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम इस क्षेत्र के विकास और इसके प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में कुछ प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

श्वेत क्रान्ति – देश में दूध उत्पादन बढाने की दिशा में संगठित रूप से पहला क्रांतिकारी प्रयास वर्ष 1970 से आरम्भ हुआ जिसे हम 'श्वेत क्रान्ति' के नाम से जानते हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड प्रथम का नाम दिया गया। इसमें देश के 10 राज्यों को शामिल किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य किसानों की आय को बढाने योग्य गतिविधियों का विकास करना था। ऑपरेशन फ्लड भारतीय डेयरी उद्योग को जर्जरता की स्थिति से उबारकर सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने का पहला सुनियोजित प्रयास था।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम – इस योजना को पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता आधार पर मार्च 1993–94 में आरम्भ किया गया था। मार्च 2005 में इसे संशोधित करके सघन डेयरी विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। बाद में इस योजना को फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया।

राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम – इस योजना का पुनर्गठन फरवरी 2014 को पूर्व की चल रही चार योजनाओं के विलय के साथ किया गया। ये योजनाएं थीं – सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सहकारिताओं को सहायता तथा राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना। इस

योजना के क्रियान्वयन के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। इस योजना के दो घटक हैं–राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना, उच्च सामाजिक–आर्थिक महत्ता वाली चयनित स्वदेशी बोवाईन नस्लों का संरक्षण, विकास तथा प्रसार करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ता से किसानों तक संपर्क स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन हेतु शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण करना है। साथ ही ग्राम–स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों/उत्पादक कंपनियों को सुदृढ़ करना तथा संभावित रूप से व्यवहार्य दुग्ध परिसंघों/संघों के पुनर्वास में सहायता करना आदि है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) – बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों के किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करके इस क्षेत्र का सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों की कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार छोटे व अन्य गौण पशु प्रजाति के विकास के लिए भी सहायता देगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस मिशन के अधीन कार्यकलापों के लिए 2800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम – इस योजना को पशु रोगों, जिनसे उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, के प्रभावी नियंत्रण को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। इसका वर्ष 2014 में विस्तार करते हुए कुल 313 जिलों में लागू किया गया।

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन – इसमें सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण इकाइयां शामिल हैं। ये सभी संस्थान आनुवांशिक रूप से उन्नत संकर सांड, बछड़े, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंस के बेहतर जर्मप्लाज्म की पहचान हेतु स्थापित किए गए हैं ताकि देश में इन पशुधनों की बेहतर नस्ल की प्राप्ति हो पाए।

राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण–1) – प्रजनन और आहार के उन्नत प्रबंधन के जरिए दुग्ध उत्पादकों/किसानों की आय में वृद्धि करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी सहकारिताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2011–12 से इस योजना को शुरू किया है। यह योजना 2242 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली योजना थी जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 14 प्रमुख डेयरी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है–

भारत में दूध उत्पादन की स्थिति

वर्ष	दूध उत्पादन (मिलियन टन)
1991–92	56.03
2000–01	98.07
2010–11	121.80
2020 लक्ष्य	235.00

दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की और अधिक पहुंच बढ़ाने में सहायता करना।

डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना – देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने व स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी उपशमन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत सितम्बर 2010 में की गई। इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है जो सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक तथा अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत तक की बैंक एंडिड कैपिटल सब्सिडी के साथ बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड – इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय आणंद (गुजरात) में है। 1987 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था तथा एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था। यह संस्था योजनाओं को बढ़ावा देती है तथा सहकारी पद्धति पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। साथ ही इनके क्रियान्वयन में भी मदद करती है।

डेयरी उद्योग की चुनौतियां और समाधान

पशुपालन क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य–पोषण और पशु रोगों पर प्रभावकारी नियंत्रण, आहार और चारे की कमी आदि तमाम चुनौतियां भरी पड़ी हैं। देश में डेयरी उद्योग के सम्मुख वर्तमान में कुछ प्रमुख प्रभावी चुनौतियां निम्नलिखित हैं–

अनुसंधान और विकास – आधुनिक डेयरी उद्योग तमाम तकनीकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें अपने देश के अंदर मौजूदा स्थिति, जलवायु और अन्य कारकों के आधार पर तकनीकी विकास करने की जरूरत है। यद्यपि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं। तथापि इस दिशा में

हमारी तैयारी और भी बढ़ाने की जरूरत है। नित नई तकनीक के प्रयोग से इस क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है।

पशु चारा, पोषण और रोगों की समस्या – देश में पशुओं के चारे और पोषण की समस्या के साथ उनमें होने वाले रोगों की रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था की गई है किन्तु इस दिशा में अब भी हम पूर्णतः निदान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आज देश के कई हिस्सों में चारागाह की उपलब्धता काफी कम या नहीं के बराबर है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि खेती का ध्यान चारा उत्पादन से नकदी फसल या खाद्यान्न फसल की तरफ अधिक है। भूमि की कमी के कारण चारागाह सिमटते गए हैं। देश में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में उपलब्ध पशुचारा महज 52 प्रतिशत पशुओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यह स्थिति विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। दूसरी तरफ काफी संख्या में पशु संक्रमित और अन्य खतरनाक रोगों से ग्रसित होते हैं और मर जाते हैं। संस्थागत तंत्र के अंतर्गत शामिल पशुओं की स्थिति तो कुछ हद तक बेहतर है, किन्तु वैसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण व्यापक–स्तर पर मवेशी पालते हैं और डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनकी स्थिति अत्यंत खराब है।

दूध उत्पादन की क्षमता के बावजूद संस्थागत तंत्र से अलगाव – आज डेयरी उद्योग की प्रगति व्यापक–स्तर पर महसूस की जाती है, किन्तु देश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां किसान मवेशी पालन करते हैं और डेयरी उद्योग में सहयोग करते हैं। वे संस्थागत तंत्र से विलग हैं। ये किसान ऐसे संस्थागत तंत्र से विलग हैं जिसके द्वारा वे अधिक लाभप्रद स्थिति में खुद को महसूस कर सकें। इसके अलावा उन्हें बाजार की कीमत का लाभ भी उचित रूप में नही मिल पाता। उनका इस उद्योग में पर्याप्त शोषण भी होता है। ऐसे गांव जहां की जलवायु और अन्य स्थिति पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के लिए अनुकूल है तथापि वे इन संस्थागत तंत्रों से अलग–थलग हैं। इन लोगों को अपने जीविकोपार्जन वाले काम में संस्थागत स्रोतों से ऋण की प्राप्ति में भी काफी दिक्कत आती है। अतः जरूरत इस बात की भी है कि इन्हें ऋण प्रवाह के संस्थागत स्रोतों से जोड़ा जाए। इन क्षेत्रों की यदि पहचान कर उन्हें पर्याप्त सुविधा और संसाधन मुहैया कराए जाएं तो इसका लाभ व्यापक–स्तर पर मिल सकेगा। आज जरूरत है ऐसे क्षमता वाले क्षेत्रों का पर्याप्त रूप से दोहन किया जाए।

पशुपालकों का शोषण – देश में ऐसे तमाम किसान और पशुपालक हैं जो बाजार और डेयरी उद्योग को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उचित हक प्राप्त नहीं कर पाते। इस क्षेत्र की यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। दूध की उपलब्धता का आधार यही किसान हैं जबकि इन्हें काफी कम कीमत पर अपना दूध व्यापारियों या निजी कंपनियों के हाथों बेचना पड़ता है। इसके अलावा इनका दूध भी काफी कम खरीदा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देशभर में किसानों और पशुपालकों द्वारा उत्पादित कुल दूध का मात्र 15 प्रतिशत दूध ही संगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है। इसके अलावा इनके शोषण का एक रूप यह भी है कि सहकारी कम्पनियां जो दूध बाजार में उपभोक्ताओं को 25–26 रुपये की दर से बेचती हैं उन्हें वे किसानों से मात्र 13–14 रुपये की दर से खरीदती हैं। इस तरह से किसान लगातार ठगे हुए महसूस करते हैं और अंततः यह व्यवसाय उन्हें लाभप्रद नहीं लगता और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। उपर्युक्त समस्याओं के अलावा अन्य कई समस्याएं डेयरी उद्योग को रुग्ण बना रही हैं। आज जरूरत है पर्याप्त बेहतर नीति और निगरानी तंत्र के साथ इसके विकास के प्रयास किए जाएं।

वैसे सरकारी–स्तर पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं तथापि उन योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना जरुरी है। आज देश में किसान वैसे ही कृषिगत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब हम डेयरी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें किसान और पशुपालकों के विकास की बात भी निहित होती है।

डेयरी क्षेत्र के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला, संस्थागत तंत्र और दूसरा असंस्थागत या असंगठित तंत्र। जहां भी सहकारिता का प्रभाव पहुंचा है उससे कुछ हद तक इस उद्योग को लाभ मिला है। लेकिन जो किसान इस तंत्र से वंचित हैं उन्हें इसके दायरे में लाने और उनकी क्षमता के दोहन की जरूरत है। दूसरी तरफ, इसके अंतर्गत निहित खामियों, शोषण को दूर करना भी नितांत आवश्यक है।

देश में डेयरी उद्यम के विकास के लिए सबसे पहले निरंतर परिस्थितिजन्य अनुसंधान और विकास की बात की जानी चाहिए। आधुनिक और उन्नत किस्म की नस्लों और साथ ही डेयरी की स्थापना पर काम किया जाना चाहिए। देश में चारागाह की अनुपलब्धता के मद्देनजर आज चारा बैंक की अवधारणा प्रबल होती जा रही है। इसके लिए पर्याप्त संरचना बनाने की जरूरत है, जिसका लाभ सभी पशुपालकों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पशुधन की बीमा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी लाभ योजना किसानों को सहज और सरल रूप में उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस प्रकार इन उपायों से हमारे देश के डेयरी उद्योग की विकास गाथा में और भी नए आयाम जुड़ेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए डेयरी उद्योग का भविष्य काफी सुनहरा है।

(लेखक पी.आर.एस. लैजिस्लेटिव रिसर्च, नई दिल्ली में लैम्प फैलो हैं)
ई–मेलः gauravkumarsss1@gmail.com